वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 3 मार्च 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति:-

एनसीपीसीआर जांच रिपोर्ट में 17 वर्षीय लावण्या के उत्पीड़न की सच्चाई आई बाहर: अभाविप

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ईसाई मत में जबरन मत परिवर्तन के प्रयास के कारण लावण्या आत्महत्या मामले में जांच पर अपनी रिपोर्ट दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी जांच रिपोर्ट का स्वागत करती है जिसमें लावण्या के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को उजागर किया गया है।

ज्ञात हो कि अभाविप लंबे समय से तमिलनाडु सरकार के खिलाफ लावण्या के लिए न्याय की मांग कर रही है और शैक्षणिक संस्थानों में जबरन मतांतरण के प्रयासों के खिलाफ लगातार देश भर में आवाज उठा रही है। अभाविप ने एनसीपीसीआर में 17 वर्षीय लावण्या के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके आत्महत्या मामले की जल्द से जल्द जांच की मांग की गई थी। इसके बाद एनसीपीसीआर ने जांच प्रक्रिया शुरू की और तमिलनाडु के तंजावुर जिले का दौरा भी किया। एनसीपीसीआर की टीम ने उस स्कूल का दौरा किया जहां लावण्या को प्रताड़ित किया गया और ईसाई मत अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। जांच के संचालन से एनसीपीसीआर द्वारा जारी रिपोर्ट में लावण्या के आत्महत्या मामले के संबंध में कई तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "नाबालिग को ईसाई मत में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया जा रहा था" और सबूतों को हटाने के लिए अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल किए गए विभिन्न तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एनसीपीसीआर द्वारा की गई जांच की सराहना करती है।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा, “लावण्या के लिए अभाविप की लड़ाई परिणाम दे रही है। नाबालिग लावण्या की आवाज अब अनसुनी नहीं रही और सच्चाई अपना रास्ता तलाश रही है। एनसीपीसीआर ने पूरे मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई है। साक्ष्य मिटाने में पुलिस की भूमिका भी सामने आ रही है। शैक्षिक परिसरों में जबरदस्ती मतांतरण के बारे में बहुत कुछ है जो राष्ट्र को लावण्या के मामले की जांच से पता चल जाएगा। ”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)